vinetur

बजट से पहले ब्रिटिश पब समूह ने यूके से पबों पर VAT 10% करने की अपील की

संस्थान ने कहा कि 40% सदस्य उम्मीद करते हैं कि अगर कर का बोझ फिर बढ़ा, तो उन्हें बंद होना पड़ सकता है।

मंगलवार, 29 सितंबर 2026



ब्रिटिश इंस्टीट्यूट ऑफ इनकीपिंग ने 28 अक्टूबर के बजट से पहले यूके सरकार से सभी पब बिक्री पर मूल्य वर्धित कर 10% करने की अपील की है। संगठन का कहना है कि कई संचालक बेहद कम मुनाफे के साथ लंबे घंटे काम कर रहे हैं और उसने चेतावनी दी है कि अगर कर फिर बढ़े तो और बंदियां हो सकती हैं।

उद्योग निकाय ने यह दलील अपने मुख्य कार्यकारी स्टीव एल्टन के प्रधानमंत्री किएर स्टार्मर और चांसलर रैचेल रीव्स को लिखे पत्र में दी, यह एक सर्वेक्षण के बाद आया जिसमें BII सदस्यों ने क्षेत्र भर में जारी वित्तीय दबाव की ओर इशारा किया। संगठन के अनुसार, अल्टन द्वारा व्यापार के लिहाज से मजबूत गर्मी बताए जाने के बावजूद, जनवरी से अगस्त के बीच केवल 25% पबों ने मुनाफा कमाया था।

वही सर्वेक्षण में पाया गया कि 20% उत्तरदाताओं को उम्मीद है कि यदि मौजूदा संयुक्त कर बोझ बना रहा, तो उन्हें बंद

होना पड़ सकता है। BII ने कहा कि अगर कर फिर बढ़े, तो यह आंकड़ा 40% तक पहुंच जाता है। अल्टन का तर्क था कि मौजूदा दबाव देश भर के कस्बों, शहरों और गांवों में आर्थिक और सामाजिक भूमिका निभाने वाले व्यवसायों में निवेश को सीमित कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि कर्मचारी लागत, ऊर्जा बिल और जिने उन्होंने अनुचित संचयी कराधान कहा, वे उन व्यवसायों को कमजोर कर रहे हैं जिन पर समुदाय निर्भर हैं। उन्होंने यह भी कहा कि पब में खर्च किए गए प्रत्येक पाउंड का लगभग 40% अब राजकोष में चला जाता है, और यह स्तर नौकरियों, नवीनीकरण और स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं पर खर्च को रोक रहा है।

BII ने कहा कि उसके सदस्य कम VAT दर पर तुरंत प्रतिक्रिया देंगे। सर्वेक्षण के अनुसार, यदि सभी पब बिक्री पर VAT घटाकर 10% कर दिया जाए, तो 75% उत्तरदाताओं ने कहा कि वे अपने व्यवसायों में निवेश करेंगे। एक और 62% ने कहा कि वे स्टाफ के घंटे बढ़ाएंगे और अपनी टीमों का विस्तार करेंगे, जबकि 50% ने कहा कि वे स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं के साथ अधिक खर्च करेंगे।

यह मुद्दा पेय उद्योग के लिए व्यापक महत्व रखता है, क्योंकि VAT सीधे उन कीमतों को प्रभावित करता है जो पब वसूलते हैं और स्थल पर उपभोग के लिए बेची जाने वाली बीयर, वाइन और स्पिरिट्स पर उनका मार्जिन तय करता है। कम दर संचालकों पर दबाव घटाने, ग्राहक मांग को सहारा देने और ब्रुअरों, वाइनरी, डिस्टिलरों तथा अन्य आपूर्तिकर्ताओं तक जाने वाले ऑर्डरों को बनाए रखने में मदद कर सकती है। अगर बंदियां जारी रहीं, तो इसका असर विपरीत दिशा में जा सकता है और ऑन-ट्रेड बिक्री केंद्रों की संख्या घट सकती है।

अल्टन ने कहा कि सरकार को बजट का उपयोग करके पबों को, उनके शब्दों में, एक न्यायसंगत सौदा देना चाहिए, जिसमें 10% VAT दर पैकेज के केंद्र में हो। उन्होंने कहा कि अगर कर नीति उन्हें ऐसा करने की गुंजाइश दे, तो संचालक निवेश करने, अपनी टीमों का विस्तार करने और नजदीकी व्यवसायों पर अधिक खर्च करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि लंबे समय से चल रहे पबों को खोने का मतलब होगा स्थानीय नौकरियों का नुकसान, आपूर्तिकर्ताओं को कम समर्थन और समुदायों में लोगों को एक साथ लाने वाले कम स्थल।

यह हस्तक्षेप ऐसे समय आया है जब #VATsTheProblem अभियान आतिथ्य व्यापार में समर्थन जुटाना जारी रखे हुए है। BII ने कहा कि कई उद्योगीय आवाजों के समर्थन वाले इस अभियान को लगभग 390,000 हस्ताक्षर मिल चुके हैं। 800 से अधिक व्यवसायों ने भी अभियान के माध्यम से आयोजित एक अलग खुले पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें इस क्षेत्र के लिए कम VAT दर की मांग की गई है।

यह ताजा दबाव सरकार पर और बोझ डालता है, क्योंकि आतिथ्य संचालक शरदकालीन राजकोषीय वक्तव्य की तैयारी कर रहे हैं। पब समूहों और व्यापार निकायों ने महीनों से तर्क दिया है कि यह क्षेत्र मजदूरी लागत, ऊर्जा खर्च, कर्ज और करों के कठिन मिश्रण का सामना कर रहा है, ऐसे समय में जब उपभोक्ता खर्च असमान बना हुआ है। BII का पत्र VAT राहत को मौजूदा स्थलों की रक्षा करने और भर्ती तथा पूंजीगत सुधारों पर खर्च को बढ़ावा देने के एक तरीके के रूप में पेश करता है।

सरकार ने अभी तक पबों के लिए VAT नीति में किसी बदलाव की घोषणा नहीं की है। फिलहाल, संचालक बजट पर करीबी नजर रखे हुए हैं, क्योंकि वे ठंडे महीनों की ओर बढ़ रहे हैं, जब कारोबार अक्सर अधिक चुनौतीपूर्ण हो जाता है और स्थिर लागतें ऊंची बनी रहती हैं।